

फरीदाबाद मजदूर समाचार

मजदूरों की मुक्ति खुद मजदूरों का काम है ।

दुनिया को बदलने के लिए मजदूरों को खुद को बदलना होगा ।

RN 42233 पोस्टल रजिस्ट्रेशन L/HR/FBD/73

नई सीरीज नम्बर 38

अगस्त 1991

50 पैसे

ईस्ट इन्डिया कॉटन

मजदूरों की एक जीत

विभिन्न नामों से व शाखाओं में कपड़ा बुनने, प्रोसेसिंग व छपाई करने और सिलाई करने वाली ईस्ट इन्डिया वॉटन मिल्स फरीदाबाद की जानी-मानी कम्पनी है। फरीदाबाद में 1977-79 के मजदूर उभार के समय ईस्ट इन्डिया के मजदूर अगवा कतारों में थे। मजदूरों के इस उभार को कुचलने के लिए ईस्ट इन्डिया मैनेजमेंट ने वह गुन्डागर्दी की कि यह मैनेजमेंट फरीदाबाद-भर में कुर्यात हो गई। अक्टूबर 79 में पुलिस ने मजदूरों को गोलियों से भून कर फरीदाबाद के उस मजदूर उभार को दबाने में सफरता पाई थी। ईस्ट इन्डिया मैनेजमेंट उस छून-खराबे के बाद कुछ अधिक ही नंगा नाची है। दाल फराई नाम वाले अपने मुन्डा गिरोह के जरिए पिछले 12-13 साल से यह मैनेजमेंट विभिन्न प्रकार की मजदूर हलचलों को कुचलने में कामयाब हुई है। ईस्ट इन्डिया मैनेजमेंट ने 1983 में अपनी जूट मिल बन्द कर दी और वहाँ से निकाले 900 मजदूरों को अब तक उनका हिसाब तक नहीं दिया गया है। ईस्ट इन्डिया भी इस कुर्यात मैनेजमेंट के खिलाफ पावरलूम के कुछ मजदूरों ने एक जीत हासिल की है। इस मैनेजमेंट के हव्वे को कुछ हद तक इन मजदूरों ने दूर किया है और अपने साथी मजदूरों के लिए राह खोली है।

हरियाणा में शासक पार्टी ने चुनावी चाल के तौर पर जून 89 से न्यूनतम वेतन के नये ग्रेडों की घोषणा की। इसके खिलाफ कई मैनेजमेंटों ने हाई कोर्ट में केस कर दिया। ईस्ट इन्डिया मैनेजमेंट भी उनमें एक थी। केस की आड़ में मैनेजमेंट द्वारा नये ग्रेड लागू नहीं करने के खिलाफ नवम्बर 89 में भी ईस्ट इन्डिया मजदूरों ने वेतन नहीं लेने जैसे सामूहिक कदम उठाये थे तथा इस पर इन मजदूरों की तनखा कुछ बढ़ा दी गई थी। मई 90 में हाई कोर्ट में फैसला हुआ : हरियाणा सरकार और मैनेजमेंटों के वकीलों ने नये ग्रेड जून 89 की जगह जनवरी 90 से लागू करने का समझौता किया था—न्यूनतम वेतन 41 केश लड़ने के लिए हाई कोर्ट में वकील खड़ा करने के नाम पर फरीदाबाद में भी यूनियनों ने मजदूरों से काफी पैसा बटोरा था पर उन्होंने इस केस में हाई कोर्ट में कोई वकील खड़ा नहीं किया। इस प्रकार हरियाणा में मजदूरों का करोड़ों रुपया मैनेजमेंटों व शासक पार्टी के नेताओं की जेबों में और लाखों रुपए यूनियन नामधारी बिचौलियों की पाकेटों में गया। खैर।

हाई कोर्ट में हुए समझौते के बाद ईस्ट इन्डिया के पावरलूम के कुछ मजदूरों ने पाया कि नये ग्रेड के अनुसार उनका जो न्यूनतम वेतन स्केल बनता है उसके अनुसार मैनेजमेंट उन्हें तनखा नहीं दे रही। डरते-भिकते हुये इस प्रकार के लगभग 100 मजदूर अलग-अलग व समूहों में मैनेजमेंट अधिकारियों व यूनियन लीडरों से मिले पर उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इस पर अक्टूबर 90 में इन 100 मजदूरों ने लिख कर मैनेजमेंट से मांग की कि उन्हें वेतन में जो 65 रुपये कम दिए जा रहे हैं उनका भुगतान किया जाए। मैनेजमेंट ने कोई जवाब नहीं दिया महीने-भर बाद यूनियन लीडरों ने इन मजदूरों को कहा कि उनका जो बनता है उसी हिसाब से उन्हें वेतन दिया जा रहा है।

12-13 साल की खुली गुन्डागर्दी के मद्देनजर पावरलूम के इन मजदूरों ने डरते-डरते दस्तखत करके मैनेजमेंट से मांग की थी। अब इन मजदूरों ने दूसरा कदम उठाया। नवम्बर 90 में इस सम्बन्ध में इन 100 मजदूरों ने डी एल सी को आवेदन दिया। ईस्ट इन्डिया मैनेजमेंट हरकत में आई। इन मजदूरों के एडवांस और कोआपरेटिव स्टोर से राशन पर मैनेजमेंट ने रोक लगा दी। धमकियों का सिलसिला भी चला पर यह मजदूर भुके नहीं। डी एल सी द्वारा बुलाई कई मीटिंगों में तो मैनेजमेंट उपस्थित

ही नहीं हुई और जब उपस्थित हुई तब उनके प्रतिनिधि न साफ-साफ कह दिया कि सरकारी ग्रेड के हिसाब से उन मजदूरों को 65 रुपये प्रतिमाह और दिए जाने चाहिए पर मैनेजमेंट नहीं देगी क्योंकि सवाल उन 100 मजदूरों का ही नहीं था बल्कि पाँच हजार मजदूरों को कंट्रोल करने का था। मजदूर स्वयं कदम उठाये और अपनी मांगें हासिल करे यह मैनेजमेंट को मंजूर नहीं था। ईस्ट इन्डिया मैनेजमेंट के प्रतिनिधि ने बीसियों मजदूरों के सामने खुल कर कहा कि मैनेजमेंट सुप्रीम कोर्ट तक जायेगी पर उन्हें पैसे नहीं देगी। डी एल सी और लेबर इन्स्पेक्टर की जिम्मेदारी थी कि वे ईस्ट इन्डिया मैनेजमेंट के खिलाफ न्यूनतम वेतन भुगतान अधिनियम के तहत कार्रवाही करें पर उन्होंने ऐसी कार्रवाही नहीं की। अनसुना कर रही। मना कर रही मैनेजमेंट को डी एल सी रिवेस्ट करता रहा और कागज लेबर इन्स्पेक्टर को बढ़ाता रहा।

इन हालात में इन 100 मजदूरों ने दिसम्बर 90 में पेटेंट ऑफ वेजेज अधिकारी के सम्मुख जनवरी 90 से बकाया वेतन के लिए केस दायर किया। इन मजदूरों ने किसी को अथॉरिटी लेंटर नहीं दिया, कोई वकील नहीं किया, किसी यूनियन लीडर को आगे नहीं किया। शिफ्टों के हिसाब से 20-30 मजदूर केस की हर तारीख पर उपस्थित हुए। और यह सब इन मजदूरों ने पेटेंट ऑफ वेजेज अधिकारी तथा लेबर डिपार्टमेंट के अन्य अफसरों व कर्मचारियों की सलाह के खिलाफ किया। यह कदम इन मजदूरों ने वकीलों व कई अन्य सलाहकारों की सलाह के खिलाफ उठाया। बिचौलियों द्वारा पहुँचाई चोटों से कुछ सबक ले कर इन मजदूरों ने कानूनी पचड़ों व अन्य शस्त्रों को स्वयं झेलने के लिए यह कदम उठाये।

फरवरी 91 में यह मजदूर डी सी से भी मिले पर डी एल सी को रेफर के सिवा और कोई रिजल्ट नहीं निकला। मैनेजमेंट ने इन मजदूरों को मड़काने के लिए उकसावेबाजों को भी आजमाया पर यह मजदूर चक्कर में नहीं आये। डी एल सी — लेबर इन्स्पेक्टर द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत ईस्ट इन्डिया मैनेजमेंट के खिलाफ केस नहीं करने पर इन मजदूरों ने स्वयं इस प्रकार का केस भी मई 91 में दायर किया।

ईस्ट इन्डिया के पावरलूम के 100 मजदूरों द्वारा बकाया वेतन के लिए दिसम्बर 90 में दायर केस को पेटेंट ऑफ वेजेज अधिकारी ने खारिज करके, रिजेक्ट करके फैसला 24 जुलाई 91 को भेजा और 24 जुलाई 91 को ही ईस्ट इन्डिया मैनेजमेंट ने 65 रुपये महीना के हिसाब से 8 महीनों का बकाया वेतन इन मजदूरों को बांट दिया।

मैनेजमेंट, बिचौलिए, लेबर डिपार्टमेंट, प्रशासन, पूँजीवादी कानून आदि की हकीकत की एक झलक तो इस घटनाक्रम में दिखाई दी ही है, मजदूरों द्वारा स्वयं पर भरोसा करके कदम उठाने के फायदों की एक झलक भी यहाँ नजर आई है। इन मजदूरों ने ईस्ट इन्डिया मैनेजमेंट से बीस-तीस लाख रुपये झटक लिये हैं और पावरलूम के आटो के मजदूरों के लिए भी इतने रुपये मैनेजमेंट से वसूल करने की राह खोल दी है। सांप से ज्यादा खतरनाक साँप की दहशत होती है—पावरलूम के इन मजदूरों ने ईस्ट इन्डिया मैनेजमेंट हव्वे की कुछ हवा निकाल कर मजदूर आन्दोलन की राह से एक रोड़ा हटाया है।

—X—

हमारे लक्ष्य हैं:— 1. मौजूदा व्यवस्था को बदलने के लिये इसे समझने की कोशिशें करना और प्राप्त समझ को ज्यादा से ज्यादा मजदूरों तक पहुंचाने के प्रयास करना। 2. पूँजीवाद को दफनाने के लिए जरूरी दुनिया के मजदूरों की एकता के लिये काम करना और इसके लिये आवश्यक विश्व कम्युनिस्ट पार्टी बनाने के काम में हाथ बटाना। 3. भारत में मजदूरों का कान्तिकारी संगठन बनाने के लिये काम करना। 4. फरीदाबाद में मजदूर पक्ष को उभारने के लिये काम करना।

समझ, संगठन और संघर्ष की राह पर मजदूर आन्दोलन को आगे बढ़ाने के इच्छुक लोगों को ताल-मेल के लिये हमारा खुला निमन्त्रण है। बातचीत के लिये बेझिझक मिलें। टीका टिप्पणी का स्वागत है—सब पत्रों के उत्तर देने के हम प्रयास करेंगे।

संपर्क—मजदूर लाइब्रेरी, आटोपिन भुम्बी, बाटा चौक के पास, एन. आई. टी. फरीदाबाद 121001

कुछ बातें जिनका मतलब समझने की जरूरत है

1. केल्विनेटर मजदूरों को एस्कोर्ट्स मजदूरों के समर्थन की एच एम एस के फरीदाबाद में प्रमुख लीडर ने बढ़-चढ़ कर बातें की थी। 21 मई को केल्विनेटर मैनेजमेंट ने तालाबन्दी करके केल्विनेटर मजदूरों पर हमला बोला। एस्कोर्ट्स में कोई हलचल देखने में नहीं आई। केल्विनेटर में लॉकआउट को पचास दिन होने को आए तब बड़े-बड़े पोस्टर लगा कर कुछ संगठनों ने दस जुलाई को साँय पाँच बजे पहली आमसभा की। एस्कोर्ट्स के प्लांटों में साढ़े चार बजे छुट्टी होती है। बारह हजार से अधिक मजदूरों वाले एस्कोर्ट्स के किसी भी प्लांट से दस जुलाई की मीटिंग में पचास मजदूरों का भी जलूस नहीं आया.....

केल्विनेटर मजदूरों की भागेदारी की वजह से बनी पाँच-सात हजार की उस मीटिंग में एच एम एस — बी एम एस—एटक—सीडू के लीडरों ने खूब भाषण झाड़ें। यूनियन लीडरों ने कहा कि (तालाबन्दी के पचास दिन बाद की पहली) आमसभा तो एकता दिखाने के लिए थी। संघर्ष का कार्यक्रम लीडर लोग दो-चार दिन बाद बैठ कर तय करेंगे.....

2 सपना-सौभाग टेक्सटाइल में एटक की अगुआई में 15 जुलाई से हड़ताल है। 31 जुलाई को एटक की यूनियनों की सपना-सौभाग के गेट पर मीटिंग रखी गई। बाटा में एटक की यूनियन है। बाटा में साढ़े चार बजे छुट्टी होती है। बाटा यूनियन ने दोपहर गेट मीटिंग में घोषणा की कि साढ़े पाँच बजे बाटा फेक्ट्री से सपना-सौभाग के गेट पर जलूस जायेगा.....

3. ऑटोपिन मैनेजमेंट ने साल-भर से गुन्डागर्दी के लिये खुले छोड़े पहले लाल और फिर हरा झन्डाधारी यूनियन लीडर को जुलाई में कान पकड़ कर नौकरी से निकाल दिया। पिछले चार—पाँच साल में ही ऑटोपिन मैनेजमेंट ने पीला—तिरंगा—लाल—हरा झन्डाधारी यूनियन लीडरों के रूप में कई लोगों को ऑटोपिन मजदूरों के खिलाफ इस्तेमाल किया है और फिर उन्हें दूध में से मक्खन की तरह निकाल कर फेंक दिया है.....

—X—

भिलाई

भिलाई स्टील प्लांट के इर्द-गिर्द के इन्डस्ट्रियल एरिया में मजदूरों का संघर्ष जारी है। 25 जून की सुबह छत्तीसगढ़ डिस्टीलरीज के निकाले हुए मजदूरों के जलूस पर पुलिस ने लाठियाँ और फिर गोलियाँ चलाई। 150 मजदूर घायल हुए, 107 मजदूर गिरफ्तार किये गये। इस हमले के खिलाफ 25 जून को ही दोपहर को दो हजार मजदूरों ने जलूस निकाला और एक सौ फेक्ट्रियों के मजदूरों ने सैकेंड शिफ्ट में हड़ताल की। मजदूरों के बल पर खड़े और भिलाई से अस्सी किलोमीटर दूर लोहा खदानों में स्थित शहीद अस्पताल के लोगों ने घायल मजदूरों की देखभाल की। जिन फेक्ट्रियों में 26 जून की छुट्टी नहीं थी उनमें उस दिन भी हड़ताल हुई। दल्ली राजहरा लोहा खदानों के मजदूरों ने पुलिस फायरिंग और लाठीचार्ज के खिलाफ जलूस निकाला। मुख्यतः यह मजदूरों द्वारा मजदूरों का सह-योग ही है जिसके बल पर अधिकतर कंपुल व ठेकेदारों के मजदूरों का भिलाई में यह संघर्ष दस महीनों से जारी है और मैनेजमेंट-सरकार गिरोह से टक्कर ले रहा है।

—O—

थॉमसन प्रेस

थॉमसन प्रेस कार्पा समय से संकट में है। पहले चोटाला और फिर लॉकआउट प्रकरण मरीज की हड़बड़ाहट के लक्षण थे। हर मर्ज की दवा का पूँजीवादी नुस्खा है : मजदूरों की बलि। लगातार यही नुस्खा इस्तेमाल करती आ रही थॉमसन मैनेजमेंट अब मजदूरों के शीश कलम करने की तैयारी कर रही है।

दो महीनों से पीने दो सो परमानेंट मजदूरों को थोखला ट्रांसफर कर ठाली बेंठाना+सो के करीब परमानेंट मजदूरों को फरीदाबाद में ठाली बेंठाना+ठेकेदारों के वर्कर्स से काम करवाना+दो शिफ्ट में काम हो सकता है पर तीन शिफ्ट करके महीने में हफ्ते-भर मजदूरों को खाली बेंठाना+सन्देश साफ है : थॉमसन मैनेजमेंट बड़े पैमाने पर छटनी की तैयारी कर रही है। मैनेजमेंट पहले धार पर लाटरी बिभाग के वर्कर्स को रखती लगती है लेकिन नम्बर औरों का भी है अपनी रोजी पर मण्डरा रहे खतरे के खिलाफ थॉमसन मजदूरों द्वारा कदम न उठाना बिल्ली को देख कबूतर द्वारा आँख मूंदने के समान है। इस सम्बन्ध में थॉमसन मजदूरों से विचार-विमर्श का हम स्वागत करेंगे।

—O—

मजबूत देश का मतलब

दिवालियेपन के कागार पर खड़े भारत को संकट से उबारने और उसे एक मजबूत देश बनाने के लिए नई नीतियों की आजकल खूब चर्चा हो रही है।

इस संविधान के दायरे में—नये संविधान की जरूरत—यूनियादी परिवर्तन के लिए खुनी क्रान्ति आदि आदि वाले इन्द्रधनुष की धुरी अथवा लक्ष्य भारत को एक मजबूत देश बनाना है। इसके वास्ते मजदूरों व अन्य मेहनतकशों से विभिन्न प्रकार की कुर्बानियाँ माँगी जाती रही हैं, माँगी जा रही हैं। आइए मामले को थोड़ा कुरेद कर देंगे।

पहली बात : यह कोई “भारतीय” विशेषता नहीं है। रूस-जर्मनी-इंग्लैंड-ब्राजील-मिश्र-ईरान-वर्मा... दुनियाँ के हर हिस्से में करीब सौ साल से यह घटनाक्रम दोहराया जा रहा है। दूसरी बात अधिक महत्वपूर्ण है : भारत नाम की कोई समरस चीज नहीं है। भारत में भी एक बड़ा हुआ समाज है। यहां भी मजदूरों और पूँजी के नुमाइन्दों के हित एक दूसरे के विपरीत हैं। भारत के हित का मतलब यहां के पूँजीवादी हित हैं।

इतिहास में राष्ट्र देश रूपी राजनीतिक इकाइयाँ मन्डी के लिये उत्पादन के माफिक उभरी, जहां स्वयं मनुष्य की श्रम-शक्ति बिक्री के लिए एक वस्तु बन जाती है, उस पूँजीवादी उत्पादन द्वारा राष्ट्र—देश स्थापित हुए। और लगभग सौ साल से यह पूँजीवादी व्यवस्था मरणासन्न—पतनशील अवस्था में पहुँच गई है। इस दौरान के पूँजीवादी व्यवस्था के संकट अपने को राष्ट्रों—देशों के संकटों के तौर पर भी अभिव्यक्त कर रहे हैं।

इसलिए देश को संकट से उबारने, देश की एकता-अखंडता की रक्षा करने, देश का विकास करने, देश को मजबूत करने आदि-आदि का मतलब आज पूँजीवाद के चरमरा रहे राजनीतिक खोल की मरम्मत करना है।

प्रोडक्शन की हमारी शक्तियाँ आज इतनी विकसित हो गई हैं कि प्रत्येक मनुष्य के लिए हंसी-खुशी भरा खुशहाल जीवन सम्भव हो गया है। लेकिन प्रोडक्शन की इन शक्तियों का मानव हित में इस्तेमाल विश्व आधार पर ही किया जा सकता है। इसलिए देशों को तोड़ कर विश्व साम्यवादी समाज का निर्माण अब इन्सानों की जरूरत बन गया है।

—O—

केल्विनेटर

मैनेजमेंट के तालाबन्दी वाले हथियार का मजदूर जवाब नहीं दे पाये इसलिए 18 जुलाई को मैनेजमेंट की शर्त पर अपने सब सौ साथियों को बाहर छोड़ कर मजदूरों को ड्यूटी पर जाना पड़ा।

अम्बी गली में फंस जाने पर बाहर निकलने के लिए केल्विनेटर मजदूर भुके पर टूटे नहीं। इसका शानदार सबूत मजदूरों ने पुलिस की गुन्डागर्दी के खिलाफ टून डाउन करके दिया है।

दो महीने की तालाबन्दी और उसके बाद की घटनायें साफ-साफ दिखा रही हैं कि मैनेजमेंट व सरकार एक तरफ हैं तो मजदूर दूसरी तरफ हैं—मैनेजमेंट में अथवा सरकार में अपने पक्षधर ढूँढना मजदूरों के लिए दल-दल में घंसने की राह है। संघर्ष के तौर-तरीकों पर गम्भीरता से विचार करने की जरूरत है। मैनेजमेंट-सरकार गिरोहबन्दी के खिलाफ काम-याबी के लिए केल्विनेटर मजदूरों की एकता तो जरूरी है ही, केल्विनेटर मजदूरों और फरीदाबाद की अन्य फेक्ट्रियों के मजदूरों का आपस में मिल कर कदम उठाना भी जरूरी है।

हां फरीदाबाद के ही आठ-दस साल के ऊषा-स्विनिंग-भारतीय इलेक्ट्रिक स्टील-ईस्ट इन्डिया-हैदराबाद एस्वेस्टोज आदि-आदि के अनुभव से सबक ले कर केल्विनेटर मजदूरों को दो-चार लोगों द्वारा इधर-उधर मार-पीट वाले कदमों से बचना चाहिए। इस प्रकार के कदम मैनेजमेंट-सरकार गिरोहबन्दी को बहाने देते हैं। पुलिस रूपी संगठित गुन्डों तथा फुटकर गुन्डों को नंगा नाचने के लिए बहाने-भर की ही जरूरत होती है। मजदूरों की राह एकता, आँखों वाली एकता और हमलों के खिलाफ सामूहिक कदमों वाली राह है।

केल्विनेटर में हालत लम्बी खीच-तान के बन गये लघते हैं। हमारे विचार से ऐसे में आर-पार की लड़ाई वाले कदमों की बजाय गले में फंसी हड्डि, जिसे न जगल सके न निगल सके, वाले कदम उपयोगी होंगे। मजदूरों द्वारा एक के बाद दूसरी डिमांड पर मैनेजमेंट को झुकते देना जहाँ मजदूरों की एकता को मजबूत करेगा वहीं मैनेजमेंट से लगातार कुछ झुकने में भी केल्विनेटर मजदूर सफल होंगे। विचार-विमर्श का हम स्वागत करेंगे।

—O—

★ मार्क्सवाद शीर्षक लेखमाला की किस्त अगले अंक में।
यहाँ नहीं दे पाने का हमें खेद है।